

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिया

भारतीय बस्ती

बस्ती 19 जून 2024 बुधवार

सम्पादकीय

रेल हादसे और तंत्र

हर बड़े हादसे को भूल जाना हमारी नीयति बन चुकी है। आये दिन रेल हादसों के बाद कुछ दिन के शोर शराबों, आरोप, आश्वासन, मुआजजा के बाद तंत्र तब तक सोता रहता है जब तक कि कोई बड़ा हादसा न हो जाय। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो गई और अनेक घायल हो गये। आखिर इन स्थितियों के लिये कौन जिम्मेदार है। सुरक्षित यात्रा के लिये रेल विभाग का दावा एक बार फिर तार-तार हो गया है।

पिछले कई वर्षों से रेल सेवाओं को सुंदर, सुरक्षित और सुविधानजक बनाने के दावे बढ़-चढ़ कर किए जाते रहे हैं, मगर रेल हादसों को रोकना अब भी चुनौती है। वर्ष भर पहले ही ओडीशा के बालासोर में तीन गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं, जिसमें दो सौ नब्बे से अधिक लोग मारे गए। अब पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें करीब पंद्रह लोगों के मरने और सात से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। पीछे के मुजिम डिब्बों में टक्कर लगी और वे पटरी से उतर गए उनमें से दो सामान और गाँड़ का डिब्बा थे। अगर उनमें भी सुराफिर रहे होते तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा होता। इस दुर्घटना के पीछे स्वचालित सिग्नल प्रणाली का खराब होना कारण बताया जा रहा है। जैसा कि हर दुर्घटना के बाद मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की जाती है, वह औपचारिकता निभा दी गई है, मगर असली वजह का पता नहीं चल पाया है। जिस रेल लाइन पर यह हादसा हुआ, वह पूर्वोत्तर का सबसे व्यस्त मार्ग है। कहा जा रहा है कि इस मार्ग पर अभी टक्कररोधी उपकरण कवच नहीं लगा है, वरना यह हादसा न होने पाता।

हर रेल हादसे के बाद नियम-कायदों के उल्लंघन, तकनीकी खामियों आदि को लेकर मंथन चलता रहता है और आखिरकार उस पर पर्दा डाल कर किनांर कर दिया जाता है। अगर रेल विभाग सचमुच रेल दुर्घटनाएं रोकने को लेकर गंभीर होता, तो एचई मामूली लापरवाहियों और तकनीकी खामियों की जगह से ऐसे बड़े हादसे न होने पाते। ट्रेनों में टक्कररोधी उपकरण लगाने का प्रस्ताव करीब पच्चीस साल पुराना है। वर्तमान सरकार ने इसके लिए कवच नामक उपकरण विकसित किया और बढ़-चढ़ कर दावा किया गया कि इस उपकरण से रेल हादसे पूरी तरह रोके जा सकेंगे।

हकीकत यह है कि अभी तक केवल डेढ़ हजार किलोमीटर रास्ते में इस उपकरण को लगाया जा सका है। हालांकि रेल हादसे केवल गाड़ियों के टकराने से नहीं होते। कभी रेल की पटरियां उखड़ जाने से डिब्बे उतर जाते हैं, तो कभी गलत पटरी पर गाड़ियों को रवाना कर दिया जाता है, कभी सिग्नल प्रणाली ठीक न होने से गाड़ियां स्टेशन छोड़ कर आगे बढ़ जाती हैं। ज्यादातर हादसे व्यस्त मार्गों और तेज राफत गाड़ियों में ही देखे जाते हैं।

विचित्र है कि देश में बुलेट ट्रेन चलाने का नक्शा खींचा जा रहा है, वंदेभारत जैसी तेज रफतार गाड़ियां बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, मगर पटरियों को सुगम बनाने के लिए एक जरूरी संसाधन चाहिए, वे नहीं जुटाए जा रहे। असुरक्षित पटरियों और कमजोर संचालन प्रणाली के जरिए मुसाफिरों को सुरक्षित सफर मुहैया कराना चुनौती ही रहेगा। लगातार हादसों के बाद जिस तरह रेलमंत्री के कामकाज के तरीके पर गंभीर सवाल उठे थे, अपेक्षा की जाती थी कि उनमें सुधार किया जाएगा।

मगर नई सरकार में भी उन्हीं को रेलवे की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब भी सब कुछ पुराने ढर्रे पर दिख रहा है। हालांकि वे तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए, पर इतने भर से सरकार की संजीवनी साबित नहीं होती, जब तक कि वह रेल सुखा से जुड़े बुनियादी पहलुओं पर गंभीरता नहीं दिखाती। देश में एक रेल हादसे के बाद रेलमंत्री के इस्तीफा देने का भी उदाहरण रहा है। लोग भरोसा करके रेलगाड़ी से अपने गंतव्य के लिए चलते हैं, मगर किसी की लापरवाही की वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ती है।

प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष वैश्विक चुनौतियां



—जी. पार्थसारथी—

भले ही कुछ आलोचकों का स्वभाव है भारत की आर्थिक नीतियों पर नुक़ाबीनी करना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्य है कि अपने आर्थिक उत्थारवाद के साथ-किरी समय रहे लाइसेंस प्रभित, कोटा राज के अंत के बाद-भारत की आर्थिक वृद्धि दर तेजी से बढ़ रही है। स्वयं भारत और दुनिया भी मानती है कि इस बदलाव के मुख्य सूत्रधार अर्थ. मनमोहन सिंह थे, जिनका योगदान देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी सर्वमान्य रहा। यह गौरवलय है कि मुक्त अर्थव्यवस्था बनाने को उनके उत्थार कदम नए आगामी में बढ गए। दुनिया भी मानती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से तरक्की करती अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आकलन है कि इस साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6 फीसदी रहेगी।

हालांकि, भारत उच्च आर्थिक वृद्धि दर पाने की ओर अग्रसर है किंतु यह वास्तव में रखनी होगी कि विश्व में इसका रुतवा और प्रभावमान अधिकांशतः मजबूत आर्थिक एवं तकनीकी तरक्की से ही तय होगा। इस जरूरी आवश्यकता के चलते, एकदम साथ लगते पहलुओं से संबंध सुदृढ़ करने के अलावा भारत के समक्ष विकस्य कम ही है। इस ढंग के, जिनसे सुखा एवं शांति सुनिश्चित हो, पहिचन में लाल सागर-कास की खाड़ी से लेकर पुरब में मलक्का की खाड़ी तक के इलाके में। अब यह व्यापक तौर पर मान्य है कि जो मुख्य चुनौतियां भारत के सामने अपनी सीमाओं पर और उनसे पार हैं। वे चीन की विस्तारवादी महावाकक्षा और नीतियों से उपजी हैं।

लंबे समय तक भारत लिंग सन्तुलन खाड़ी क्षेत्र से नजदीकी रिश्ते बनाने की आकांक्षा रखता आया है, जहां पर लगभग 60 लाख भारतीय कामगार रोजी-रोटी कमा रहे हैं। एक ओर भारत ने सऊदी अरब के साथ नजदीकी संबंध स्थापित कर लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के साथ रिश्ते से अच्छे संबंधों को और प्रगाढ़ किया जा रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रिश्ते पुनः मधुर बनाने में भारत की भूमिका अहम रही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा सऊदी अरब के राजपरिवार को लेकर की गई नवावर टिप्पणी के बाद, सऊदी अरब की पलटवार बयानबाजी के बाद इनके संबंध तल्ह हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रिय सुखा सलाहकार जेफ रिस्वेल और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई वार्ता में यूएई के राष्ट्रीय सुखा



सलाहकार शैव तहनुन बिन जायद अल नाहायन भी उपस्थित थे। इन वार्ताओं के एक सूत्रधार भारत के राष्ट्रीय सुखा सलाहकार अजीत उमलाथे गौरी, अमेरिका और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने के वास्ते एक समझौता हुआ और जल्द ही अंतिम प्राप्क पर दस्तखत किए गए। अब पड़ोस के छह अरब राष्ट्रों सहित हिंद महासागर क्षेत्र के पश्चिमी किनारे तक के इलाके में उत्तरांतर सरकारतक एवं सहयोगात्मक भूमिका निभाने के लिए भारत का मंच तैयार है।

भारत-अमेरिकी संबंध तब से अधिक प्रगाढ़ हो गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने तय किया कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत से संतुलन बढाना भारत के बस की बात है और वह यह करना भी चाहेगा। दोस्ती के नाटक के बावजूद चीन की नीतियां भारत के प्रभाव को सीमित करने से बची हुई हैं। चीन पाकिस्तान के मिशाल एवं परमाणु महात्ताओं को मजबूती देने का काम जारी रखे हुए है। भारत की अफगानिस्तान की तरफ लगती पहिचनी सीमा के साथ और परे,

चीन पाकिस्तान के साथ निकट सहयोग बनाकर काम कर रहा है। ईरान के साथ रिश्ते मजबूत करने के भारत के हाथिया प्रयास, जिसमें सामरिक रूप से अहम चावहार बंदरगाह का विकास कार्य शामिल है, इससे जहां भारत को मध्य एशिया क्षेत्र और अधिक आर्थिक एवं नौवहनिय पट्टे बनाने में मदद मिलेगी, वहीं अफगानिस्तान तक भारत की पहुंच को अडो लगाने के पाकिस्तानी प्रयासों की गुजाइश कम बचेगी।

ईरान के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों पर अमेरिका ने पहले एतराज जताया था, लेकिन अब लाता है कि बाद में विचार करने पर, उसे ईरान से होकर, अफगानिस्तान के साथ जोड़ना भारत का परिहहन गलियार बनाना स्वीकार्य है। उम्मीद है इससे पाकिस्तान इस परिहहन गलियारे से खुश नहीं है, क्योंकि इससे राखलपिंडी के सेना मुख्यालय में बैठे पाकिस्तानी जनरलों को भारत की ईरान, अफगानिस्तान और आगे मध्य एशिया तक बरती पहुंच में रोडे अटकने का मौका नहीं मिलता। आगे चलकर यह गलियारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से

जुड़ने में भारत का एक अहम आवाजाही द्वार बन जाएगा, इसके होकर भारत पहले मध्य एशिया और रूस से जुड़ेगा, तो अंतिम चरण में, यूरोप तक समुद्री, रेल और सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा।

भारत-अमेरिका संबंधों पर जिस अहम कारक की छाया पड़ी है, वह है अमेरिकी मीडिया द्वारा भारत में लोकतांत्रिक आजादी पर कथित कुठाराघात को लेकर जो रही निरंतर आलोचना। आमतौर पर महसूस किया जाता है कि इस मीडिया आलोचना को राष्ट्रपति बाइडेन का समर्थन हासिल है। यह भी माना जा रहा है कि यदि साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भारत के प्रति दोस्ताना रखने वाले ट्रंप विजयी हुए तो इस किस्म की आलोचनाएं बंद हो जाएंगी। हो सकता है भारत उन कुछ देशों में एक हो, जिसके नेतृत्व अर्थ लोको को राष्ट्रपति ट्रंप मित्रता और बेबाक लगे, जब वे भारत आएंगे। चीन को लेकर दुर्घटन में न तो कोई भ्रम है न ही उन्मीद और पाकिस्तान के बारे में सोचने की तरफ भी उनका झुकाव कम ही रहा है।

बाइडेन प्रशासन की रीति के विपरीत पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भारत के लोकतंत्र के बारे में कोई उपदेश नहीं देते। तथापि अमेरिका के साथ हमारे संबंध लगातार निकट बनते गए, जिसमें भारत-अमेरिका में नौवहनिय सम्पर्क से सुदृढ़ता लाने हुए सहयोग काफी बड़ा। हिंद महासागर में बीच समुद्र जलयानों पर हमला या टूट की वारताओं से पैदा हुए तनाव के बाद यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है, ठीक इसी वक्त गाजा पर इराकली कक्षा अभियान जारी था। होरपुज की खाड़ी से लेकर मलक्का की खाड़ी तक फ्लैट हैल-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबाव के मद्देनपर अमेरिका भारत को बतौर एक महत्वपूर्ण सामरिक भागीदार मानना जारी रखे हुए है। चीन और पाकिस्तान के साथ

लैंगिक असमानता की बढ़ती खाई



—ललित गर्ग—

विश्व आर्थिक मंद द्वारा हाल में प्रस्तुत किये गए लैंगिक अंतर के आंकड़ों ने एक ज्वलंत चित्र खड़ा किया है कि शिक्षा, आय, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अभी दुनिया को उरसा कव क्यों नहीं मिल पा रहा है। शीर्ष 10 में शेष भी अर्थव्यवस्थाओं में से आठ न अपने अंतर का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा पाट लिया है। निश्चित तौर पर किसी भी समाज में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में लंबा समय लगता है, लेकिन इस दिशा में सतापीशों की तरफ से ईमानदार पहल होनी चाहिए। यह भी एक हकीकत है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के आंकड़ों की तुलना दक्षिण एशिया के उक्त देशों से नहीं की जा सकती। इसमें दो राय नहीं कि पूरी दुनिया में सरकारों द्वारा लैंगिक समानता के लिये नीतियां बनाने के बावजूद अपेक्षित प्रभाव नहीं निकले हैं। जिसकी एक वजह समाज में बावजूद अनेक प्रकार की सोच भी है। जिसके चलते यह आशावादा होता है कि आगे भी दुनिया के कल्याण के लिये बनी हुई योजनाएं महज घोषणाओं तथा फाड़ले तक सिस्टम कर रह जाती हैं।

भारत में महिलाओं की उपेक्षा, भेदभाव, अत्याचार एवं असमानता की स्थितियां का बना रहना विद्यमानापूर्ण है। भारत से रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के स्वयं तो बहुत सुझावों को मिलते हैं, महिलाओं को आजादी के बाद से ही मतदान का अधिकार भी पुरकों के बरबर दिया गया है, परन्तु यह वास्तविक समानता की बाढ़ करे तो भारत में आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति



पड़ोसी देश बांग्लादेश को 99वें, चीन को 106वें, नेपाल को 117वें, श्रीलंका को 122वें, भूटान को 124वें और पाकिस्तान को 145वें स्थान पर रखा गया है। आइसलैंड (93.5 फीसदी) फिर से पहले स्थान पर है और डेढ़ दशक से सूचकांक में सबसे आगे है। शीर्ष 10 में शेष भी अर्थव्यवस्थाओं में से आठ न अपने अंतर का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा पाट लिया है। निश्चित तौर पर किसी भी समाज में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में लंबा समय लगता है, लेकिन इस दिशा में सतापीशों की तरफ से ईमानदार पहल होनी चाहिए। यह भी एक हकीकत है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के आंकड़ों की तुलना दक्षिण एशिया के उक्त देशों से नहीं की जा सकती। इसमें दो राय नहीं कि पूरी दुनिया में सरकारों द्वारा लैंगिक समानता के लिये नीतियां बनाने के बावजूद अपेक्षित प्रभाव नहीं निकले हैं। जिसकी एक वजह समाज में बावजूद अनेक प्रकार की सोच भी है। जिसके चलते यह आशावादा होता है कि आगे भी दुनिया के कल्याण के लिये बनी हुई योजनाएं महज घोषणाओं तथा फाड़ले तक सिस्टम कर रह जाती हैं।

भारत में महिलाओं की उपेक्षा, भेदभाव, अत्याचार एवं असमानता की स्थितियां का बना रहना विद्यमानापूर्ण है। भारत से रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के स्वयं तो बहुत सुझावों को मिलते हैं, महिलाओं को आजादी के बाद से ही मतदान का अधिकार भी पुरकों के बरबर दिया गया है, परन्तु यह वास्तविक समानता की बाढ़ करे तो भारत में आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति

स्थितियां हैं। सेंटर फॉर मॉनीटोरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआई) नाम के थिक टैंक ने बताया है कि भारत में केवल 7 प्रतिशत शहरी महिलाएं एपीई हैं, जिनके पास रोजगार है या वे उसकी तलाश कर रही हैं। सीएमआई के मुताबिक, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में हमारा देश इंडोनेशिया और सऊदी अरब से भी पीछे है। रोजगार या नौकरी का जो बड़ा रिजर्वो के सराफिकरण का सबसे बड़ा जरिया रहा है, उसमें इन्की भागीदारी का अनुपात बेहद चिंताजनक हालात में पहुंच चुका है। यों जब भी किसी शहरी या समाज में अंचाक या सुनि्याजित उधल-धुलत होती है, कोई आपदा, युद्ध एवं राजनीतिक या मज्जुजनि संमस्या खड़ी होती है, तो उसका सबसे ज्यादा नकारात्मक असर स्थियों पर पड़ता है और उन्हें ही इसका खामियाखार उठाना पड़ता है।

दावों से हुए वृद्ध इकॉनॉमिक फोरम में ऑक्सफोर्ड ने अपनी क्विस्ट 'टाइम टू केयर' में घरेलू औरतों की आर्थिक स्थितियों का खुलासा करते हुए दुनिया को चौंका दिया था। वे महिलाएं जो अपने घर को समालती हैं, परिवार का ख्याल रखती हैं, वह सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अनगिनत सबसे मुश्किल कामों को करती हैं। अगर हम यह कहें कि घर समालाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो शायद गलत नहीं होगा। दुनिया में फिरक नहीं है, जिसमें 24 घंटे, सातों दिन आप काम पर रहते हैं, हर रोज काइसिंह झेलते हैं, हर डेडलाइन को पूरा करते हैं और वह भी बिना सुष्टी के। सांफिए इन्हें सारे कार्य-संपादन के बदले में वह कोई वेतन नहीं लेती। उसके परिश्रम को सामान्यतः घर का नियमित काम-काज कहकर विश्व महसूस नहीं किया जाता। साथ ही उसके नहीं दिया जाने का राष्ट्र की उन्नति में योग्यभूत होने की संज्ञा भी नहीं मिलती। इन्हें है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं के श्रम का आर्थिक मूल्यकम क्यों नहीं किया जाता? घरेलू महिलाओं के साथ यह दोगला व्यवहार क्यों? नरन्ध्र मोदी की पहल पर निश्चित ही महिलाओं पर लगा दोगला दर्जा का लेवल हट रहा है। जिस एव अत्याचार की घटनाओं में भी कमी आ रही है।

केदारनाथ आपदा से कोई सबक क्यों नहीं



—जयसिंह रावत—

केदारनाथ आपदा को गुरुरे हुए 11 साल हो गये मगर उस विभीकण के घाव अब तक नहीं पर गये। इस त्रासदी में न जाने कितने लोग मरे होंगे, इसका सटीक अनुमान नहीं ला सकें। मगर राय पुलिस द्वारा मानवधिकार आयोग को सौंपे गयी रिपोर्ट में इस आपदा में पूरे 6182 लोग लापता बताये गये। जिन साक्ष्यों का सुधुरे वाता कोई नहीं तथा देश को सुदूर हिसाली से आगे गरीब यात्रियों को कोई रिकार्ड ही नहीं था। अगर हमने केदारनाथ आपदा से कोई सबक सीखा होता तो 7 जनवरी, 2021 को सीमांत चमाली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में चीनगो और खलिंगगो की बाढ़ की तलाही नहीं होती। उस त्रासदी में कम से कम 206 लोगों के मारे जाने की कि पुष्टि हुई। खलिंगगो पर 132 मीगावट और शीलोगो पर 520 मीगावट के बिजली प्रोजेक्ट नहीं बन रहे होते तो इन नदियों की बाढ़ उन्नी हिमारेककारी नहीं होती। लगता है हमारे योजनाकार और नीति-निर्माता न तो केदारनाथ में आने ही नहीं देती।

लौरीगो की बाढ़ की विभीकणों को कोई सबक सीख सके। विकास के नाम पर सारे कार्य-संपादन के बदले में वह कोई वेतन नहीं लेती। उसके परिश्रम को सामान्यतः घर का नियमित काम-काज कहकर विश्व महसूस नहीं किया जाता। साथ ही उसके नहीं दिया जाने का राष्ट्र की उन्नति में योग्यभूत होने की संज्ञा भी नहीं मिलती। इन्हें है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं के श्रम का आर्थिक मूल्यकम क्यों नहीं किया जाता? घरेलू महिलाओं के साथ यह दोगला व्यवहार क्यों? नरन्ध्र मोदी की पहल पर निश्चित ही महिलाओं पर लगा दोगला दर्जा का लेवल हट रहा है। जिस एव अत्याचार की घटनाओं में भी कमी आ रही है।

बदरीश्वर की क्रम धारा जिले की कुछ पिछले रिकार्ड लौती जा रही है। इस साल 16 जून तक चारों गामों में 23,54,440 यानी पंद्रह चूके थे। जबकि सन् 2000 तक सटीक अनुमान नहीं ला सकें। मगर राय पुलिस द्वारा मानवधिकार आयोग को सौंपे गयी रिपोर्ट में इस आपदा में पूरे 6182 लोग लापता बताये गये। जिन साक्ष्यों का सुधुरे वाता कोई नहीं तथा देश को सुदूर हिसाली से आगे गरीब यात्रियों को कोई रिकार्ड ही नहीं था। अगर हमने केदारनाथ आपदा से कोई सबक सीखा होता तो 7 जनवरी, 2021 को सीमांत चमाली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में चीनगो और खलिंगगो की बाढ़ की तलाही नहीं होती। उस त्रासदी में कम से कम 206 लोगों के मारे जाने की कि पुष्टि हुई। खलिंगगो पर 132 मीगावट और शीलोगो पर 520 मीगावट के बिजली प्रोजेक्ट नहीं बन रहे होते तो इन नदियों की बाढ़ उन्नी हिमारेककारी नहीं होती। लगता है हमारे योजनाकार और नीति-निर्माता न तो केदारनाथ में आने ही नहीं देती।

पद्मपुरम चण्डी प्रसाद बह आदि विश्वेश्वरों के अनुसर हिमालयी तीर्थों पर उन्की धारक क्षमता से इतनी अधिक भीड़ विनाशकारी ही हो सकती है। लिता का क्षियत तो यह है कि लाता वहां सीधे गंगाजी और सतोजप नलेपियर सहूहों के पास तक पहुंच रहे हैं। जिससे इन नलेपियरों के पिचलने की गति बढने और हिमालय पर हिमनद झीलों की संख्या और आकार बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। सन् 2013 की बाढ़ में चोराबड़ी झील ही केदारनाथ को कोई सबक सीख सके। विकास के नाम पर सारे कार्य-संपादन के बदले में वह कोई वेतन नहीं लेती। उसके परिश्रम को सामान्यतः घर का नियमित काम-काज कहकर विश्व महसूस नहीं किया जाता। साथ ही उसके नहीं दिया जाने का राष्ट्र की उन्नति में योग्यभूत होने की संज्ञा भी नहीं मिलती। इन्हें है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं के श्रम का आर्थिक मूल्यकम क्यों नहीं किया जाता? घरेलू महिलाओं के साथ यह दोगला व्यवहार क्यों? नरन्ध्र मोदी की पहल पर निश्चित ही महिलाओं पर लगा दोगला दर्जा का लेवल हट रहा है। जिस एव अत्याचार की घटनाओं में भी कमी आ रही है।

केदारनाथ आपदा के कारणों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) की टीमें न स्वयं दो बार आपदाप्रस्थ क्षेत्रों का दौरा करने के साथ ही रिपोर्ट संतिय, वाडिया इस्टीमेटोर और सिलिगुम विनियोगारी भी हो सकते हैं। लिता का क्षियत तो यह है कि लाता वहां सीधे गंगाजी और सतोजप नलेपियर सहूहों के पास तक पहुंच रहे हैं। जिससे इन नलेपियरों के पिचलने की गति बढने और हिमालय पर हिमनद झीलों की संख्या और आकार बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। सन् 2013 की बाढ़ में चोराबड़ी झील ही केदारनाथ को कोई सबक सीख सके। विकास के नाम पर सारे कार्य-संपादन के बदले में वह कोई वेतन नहीं लेती। उसके परिश्रम को सामान्यतः घर का नियमित काम-काज कहकर विश्व महसूस नहीं किया जाता। साथ ही उसके नहीं दिया जाने का राष्ट्र की उन्नति में योग्यभूत होने की संज्ञा भी नहीं मिलती। इन्हें है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं के श्रम का आर्थिक मूल्यकम क्यों नहीं किया जाता? घरेलू महिलाओं के साथ यह दोगला व्यवहार क्यों? नरन्ध्र मोदी की पहल पर निश्चित ही महिलाओं पर लगा दोगला दर्जा का लेवल हट रहा है। जिस एव अत्याचार की घटनाओं में भी कमी आ रही है।

